

संसदीय कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 72

संसदीय कार्य मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	18.90	...	18.90	50.52	...	50.52	43.44	...	43.44	65.07	...	65.07
<i>वसूलियां</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>प्राप्तियां</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	18.90	...	18.90	50.52	...	50.52	43.44	...	43.44	65.07	...	65.07
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	18.90	...	18.90	50.52	...	50.52	43.44	...	43.44	25.07	...	25.07
2. राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	40.00	...	40.00
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>18.90</b>	...	<b>18.90</b>	<b>50.52</b>	...	<b>50.52</b>	<b>43.44</b>	...	<b>43.44</b>	<b>65.07</b>	...	<b>65.07</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>18.90</b>	...	<b>18.90</b>	<b>50.52</b>	...	<b>50.52</b>	<b>43.44</b>	...	<b>43.44</b>	<b>65.07</b>	...	<b>65.07</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	18.90	...	18.90	50.52	...	50.52	43.44	...	43.44	65.07	...	65.07
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>18.90</b>	...	<b>18.90</b>	<b>50.52</b>	...	<b>50.52</b>	<b>43.44</b>	...	<b>43.44</b>	<b>65.07</b>	...	<b>65.07</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>18.90</b>	...	<b>18.90</b>	<b>50.52</b>	...	<b>50.52</b>	<b>43.44</b>	...	<b>43.44</b>	<b>65.07</b>	...	<b>65.07</b>

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान संसद सदस्यों के सचिवालय स्टाफ के वेतन इत्यादि, विदेश जाने वाले संसद सदस्यों के प्रतिनिधिमंडलों हेतु व्यय, पारस्परिक आधार पर विदेशी संसदीय प्रतिनिधियों की भारत यात्रा, युवा संसद प्रतियोगिताओं के आयोजन एवं अन्य व्यय की व्यवस्था के लिए है।

2. **राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन:** सभी राज्यों के विधान मंडलों को डिजिटल हाऊसेस में बदलने के लिए नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन-एनईवीए, जोकि एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है, जिससे कि इनकी कार्य प्रणाली को पेपरलेस बनाया जा सके। इनके लिए बजट अनुमान 2020-21 और संशोधित अनुमान 2020-21 में किए गए समान प्रावधान को सचिवालय के अंतर्गत रखा गया है।